

Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No.59/2017

No. E.678/0/3/Vol.VII

Kolkata, Dated: 13/06/2017

All Concerned

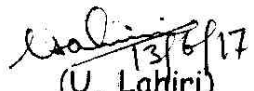
(as per standard list)

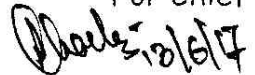
Sub: Grant of Advances - Seventh Central Pay Commission
recommendations - Discontinuance of 'Natural Calamity
Advance'.

A copy of Railway Board's letter No. E(G) 2017/AD 1-1 dated 30/05/2017 (RBE No. 52/2017) on the subject is forwarded herewith together with its enclosures, containing Advance Correction Slip (ACS) No.238 to IREM, Vol.I and Hindi version, for information, guidance, and necessary action.

In terms of the aforesaid instructions, the existing provision regarding grant of Natural Calamity Advance contained in paras 1123 and 1123(A) of IREM, Vol.I has been abolished w.e.f. 07/10/2016. The cases where the advances have already been sanctioned need not be reopened.

DA: As above.


(U. Lahiri)
Dy. Chief Personnel Officer/R
For Chief Personnel Officer

 13/6/17 Phone no.: 24103

Index No. 1028: The existing provision regarding grant of Natural Calamity Advance contained in paras 1123 and 1123(A) of IREM, Vol.I has been abolished w.e.f. 07/10/2016.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

RBE No. 52 / 2017

No.E(G) 2017/AD 1-1

New Delhi, dated 30.05.2017

**The General Managers & FA&CAOs,
All Indian Railways &
Production Units etc.
(as per standard mailing list)**

**Sub: Grant of Advances - Seventh Central Pay Commission
recommendations - Discontinuance of 'Natural Calamity Advance'.**

The Seventh Central Pay Commission vide Para 9.1.4 had recommended that all the interest-free advances being granted to the Central Government employees should be abolished. The Government's decision in this regard has been conveyed by the Ministry of Finance vide their OM No.12(1)E.II(A)/2016 dated 07.10.2016. According to the instructions contained therein, the Natural Calamity Advance in addition to six other advances has been abolished.

2. The Government's decision in respect of abolition of advance of Natural Calamity Advance has been considered by the Ministry of Railways in consultation with Finance Directorate. It has been decided to abolish Natural Calamity advance w.e.f. 07.10.2016. The cases where the advances have already been sanctioned need not be reopened.

3. The provisions in respect of Natural Calamity Advance are contained in paras 1123 and 1123(A) of Indian Railway Establishment Manual (IREM), Volume-I. In view of the above, it is directed that paras 1123 and 1123(A) of IREM may be amended as in the enclosed Advance Correction Slip No.238.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Please acknowledge receipt.

DA: Correction Slip.


(D. Joseph)
Dy. Dir./E(G)III
Railway Board

Contd...p/2

**ADVANCE CORRECTION SLIP TO THE INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT
MANUAL VOLUME-I**

Advance Correction Slip No.238.

The following amendments may be made to Para 1123 and 1123(A) of the Indian Railway Establishment Manual, Volume-I :-

Para 1123 and 1123(A) may be substituted as under:-

Para 1123 and 1123(A) Natural Calamity Advance

The provisions stand deleted as the advance in this regard has been abolished by the Seventh Pay Commission.

(Authority : Railway Board's letter No.E(G)2017/AD 1-1 dated 30/05/2017)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं.ई(जी)-2017/एडी1/1

नई दिल्ली, दिनांक 30.05.2017

महाप्रबंधक, विस एवं मुलेधि,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय:- अग्रिम प्रदान करना- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें-
'प्राकृतिक आपदा अग्रिम' समाप्त करना.

सातवें केन्द्रीय आयोग ने पैरा 9.1.4 द्वारा सिफारिश की थी कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जा रहे सभी ब्याज मुक्त अग्रिम समाप्त कर दिए जाए. इस संबंध में सरकार का निर्णय वित्त मंत्रालय के का.जा. सं 12(1) ई॥(ए)/2016 दिनांक 07.10.2016 द्वारा संसूचित किया गया है. इसमें निहित अनुदेशों के अनुसार, प्राकृतिक आपदा अग्रिम के अलावा छः अन्य अग्रिमों को समाप्त कर दिया गया है.

2. प्राकृतिक आपदा अग्रिम की समाप्ति के संबंध में सरकार के निर्णय पर रेल मंत्रालय द्वारा वित्त निदेशालय के परामर्श से विचार किया गया है. दिनांक 07.10.2016 से प्राकृतिक आपदा अग्रिम को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. वे मामले जिनमें अग्रिम पहले ही स्वीकृत कर दिए गए हैं फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है.

3. प्राकृतिक आपदा अग्रिम के संबंध में प्रावधान भारतीय रेल स्थापना संहिता नियमावली, जिल्द-1 के पैरा 1123 तथा 1123(ए) में है. उपर्युक्त को देखते हुए है निदेश दिया जाता है कि आई आर ई एम के पैरा 1123 और 1123(ए) में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं 238 के अनुसार संशोधन किया जाए.

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.
5. कृपया पावती दें.

संलग्न: अग्रिम शुद्धि पर्ची.

डी. जोसफ

(डी. जोसफ)

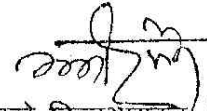
उप निदेशक/स्था.(जी)

रेलवे बोर्ड

सं.ई(जी)-2017/एडी1/1

नई दिल्ली, दिनांक 30.05.2017

प्रतिलिपि:- भारत के उप नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)


कृते वित्त आयुक्त, रेलें

प्रतिलिपि:-

1. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं. 253 रेल भवन नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एनएफआईआर कमरा न. 236-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद् एवं राष्ट्रीय परिषद् तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली. (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. महासचिव, एफआरओए, कमरा नं. 256-ए रेल भवन, नई दिल्ली. (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' अधिकारी एसोसिएशन, रेल भवन, कमरा नं. 402, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. अध्यक्ष, ग्रुप II अधिकारी एसोसिएशन, रेलवे बोर्ड
7. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 341-सी रेलवे बोर्ड
8. अध्यक्ष, भारतीय रेलवे ग्रुप II अधिकारी एसोसिएशन,

भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-1 के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.

भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-1 के पैरा 1123 एवं 1123(ए) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं:-

पैरा 1123 वं 1123(ए) को निम्नासार प्रतिस्थापित किया जाए:-

पैरा 1123 एवं 1123(ए) प्राकृतिक आपदा अग्रिम

इन प्रावधानों को हटा दिया गया माना जाए क्योंकि इस संबंध में सातवें वेतन आयोग द्वारा अग्रिम समाप्त कर दिया गया है.

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई(जी)-2017/एडी1/1, नई दिल्ली, दिनांक 30.05.2017)
